शहरी वित्त

तिमाही समाचार पत्र

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

USAID | INDIA
INDO - USAID FIRE (D) PROJECT

NIUA

4

खंड 12 सं.4
अक्टूबर–दिसम्बर 2009

विषय सूची

समापन रिट्रीटः शहरी गरीबी के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति	1
राष्ट्रीय शहरी सफाई–व्यवस्था नीति समन्वय प्रकोष्ठ	1
शहरी गरीबी अनुसंधान कार्यसूची	2
नवीनतम रिपोर्ट/परियोजनाएं	2
स्थानीय सरकार की जलवायु कार्ययोजना	2
मेट्रोपोलिसः शहरी विकास प्रबंधन	3
शहर–दर–शहर जानकारी	3
गरीबों के लिए जल एवं सफाई–व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए शहरी–मॉडलः फायर(डी) प्रयास	3
रा.न.का.सं. द्वारा आयोजित/समर्थित गतिविधियां	4

समापन रिट्रीट : शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति

शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति पर राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (रा.न.का.सं.) तथा ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (ए.आई.आई.एल.एस.जी) की सहायता से आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने 14–15 दिसम्बर 2009 को गोआ में एक रिट्रीट का आयोजन किया। इस परियोजना में रा.न.का.सं., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) तथा गरीबी उपशमन कार्यनीति (यू.पी.आर.एस.) के लिए भागीदार के रुप में शामिल था।

इस दो–दिवसीय कार्यशाला में परियोजना में शामिल समस्त संस्थानों के प्रस्तुतीकरण सम्मिलित थे। इस रिट्रीट की अध्यक्षता श्रीमती किरण ढ़ींगरा, सचिव ने की तथा उद्घोषक श्री पी. के. मोहन्ती, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय थे। अन्य प्रख्यात भागीदारों में यू.एन.डी.पी. के कंट्री हेड श्री डेडरे बायड, राज्य सचिव. डा. अभिताभ कुण्डु, श्रीमती स्नेह पलनीतकर (निदेशक आर.सी.यू.ई.एस., ए.आई.आई.एल.एस.जी.) तथा यशवन्त राव चावन एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा), इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ (आई.ई.जी.), सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (सी.जी.जी.), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्स (टी.आई.एस.एस.), मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (एम.एस.ई.) तथा सेल्फ इम्प्लाएड वूमेन्स एसोसिएशन (एस.ई.डब्लू.ए.) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्रीमती परामिता डे ने रा.न.का.सं. द्वारा तैयार किए गए 11 यू.पी.आर.एस पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रो. धर ने धन्यवाद दिया।

एन.एस.यू.पी. का उद्देश्य शहरी गरीबी के विभिन्न पहलुओं को समझना और जीवंत, व्यवहारिक एवं शहरी गरीबों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित गरीबों के लिए न्यायोचित कार्यनीति प्रस्तुत करना है।

राष्ट्रीय शहरी सफाई/व्यवस्था नीति समन्वय प्रकोष्ठ

जीवनयापन की स्वस्थ परिस्थितियों के स्वच्छ शहरों (क्लिीनर सिटीज़) के प्रयासों की दिशा में, श.वि.मं. द्वारा तैयार राष्ट्रीय शहरी सफाई–व्यवस्था नीति का उद्देश्य राज्यों को शहरी सफाई व्यवस्था की कार्यनीतियां विकसित करने तथा शहरों में सफाई–व्यवस्था योजनाएं विकसित करने में सहायता देगी। इसे प्रचालित करने के उद्देश्य से, सिटीज. एलाएन्स राष्ट्रीय शहरी सफाई–व्यवस्था समन्वय प्रकोष्ठ द्वारा प्रबंधन किया जाएगा जो राज्य व शहरी सफाई–व्यवस्था कार्यदलों के माध्यम से कार्य करेगा। यह एन.यू.एस.पी. में बताए गए मुद्दों को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय सरकारों को सहायता देगा।

प्रो. स्वर्ण वेपा, एम.एस.ई., द्वारा राष्ट्रीय यू.पी.आर.एस. प्रस्तुत किया गया। इसे सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व, कार्यनीति में सुधार करने के लिए भागीदारों ने सुझाव दिए। सचिव की अध्यक्षता में आयोजित रिट्रीट में दिखाया गया मार्ग कार्यदलों के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि आ. एवं श. ग.उ.मं. विभिन्न नीतिगत प्रयासों के माध्यम से परियोजना के अंतर्गत किए गए सतत् कार्यों के मुद्दें पर सक्रिय विचार कर रही है।

श्रीमती पारामिता डे, रा.न.का.सं.

शहरी गरीबी अनुसंधान कार्यसूची

दि बोल्फेनसोन सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट तथा रा.न.का.सं. ने शहरी गरीबी अनुसंधान कार्यसूची पर 29 अक्टूबर 2009 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट के श्री जोहेन्स एफ. लिन ने 'विकसित देशों में शहरी गरीबी की एक नई, पुरानी और भूली हुई चुनौतियां – एक अस्थायी अनुसंधान कार्यसूची' पर प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री के.सी. सिवारामाकृष्णन, अध्यक्ष सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने की थी। श्रीमती पेट्रीशिया ऐनेज़ ने जारी अनुसंधान अध्ययन तथा कार्यशाला के उद्देश्य पर जानकारी दी।

श्री जोहेन्स लिन

श्री जोहेन्स लिन ने पिछले तीस वर्षों में शहरी गरीबी कार्यसूची की परिवर्तित प्रकृति की समीक्षा की। विभिन्न मुद्दों को चुनौतियों, उपकरणों, विश्लेषणात्मक/योजना उपकरणों, आंकड़ों व बेंचमार्कों, क्षेत्रों/देशों/शहरों तथा संस्थानों में श्रेणीबद्ध व वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ पुराने मुद्दे और उपाय आज भी वैध हैं, जबकि अनेक नए मुद्दे और प्रयास हैं जिन पर अब विचार किए जाने की आवश्यकता है। ये हैं: रोजगार, लघु एवं मध्यम आकार के शहर, व्यापक स्लम उन्नयन कार्यक्रम, सशर्त नगद अंतरण कार्यक्रम, प्रोत्साहन आधारित प्रयास; खुशी एवं जीवन-संतोष अनुसंधान प्रयासों, प्रभाव-मूल्यांकन, तथा कार्यनीति योजना उपकरण।

भागीदारों में प्रो. सुनील बेरी, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, डा. पी.के. मोहन्ती, संयुक्त सचिव, आ. एवं श. गरीबी उपशमन मंत्रालय, प्रो. ओ.पी. माथुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी, श्री वी.के. फाटक, भूतपूर्व मुख्य नियोजक, मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अनुसंधान संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों, एन.जी.ओ. आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शहरी सेवाएं और जे.एन.एन.यू.आर.एम. के प्रभाव: नागपुर, राजकोट और विशाखापत्तनम का अध्ययन

यह अध्ययन वर्ष 2004 (जे.एन.एन.यू.आर.एम. से पूर्व) तथा वर्ष 2009 में मूल सेवाओं अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज, जल-निकासी और ठोस कचरा प्रबंधन की दशा की तुलना करता है। इस अध्ययन का परिणाम दर्शाता है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम के आरंभ से शहरी सेवाओं की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है।

वर्तमान में असंख्य परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका चुनिंदा शहरों में सेवाओं के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव होगा।

53 दक्षिण एशियाई शहरों के ऊर्जा और कार्बन-उत्सर्जन की रुपरेखा

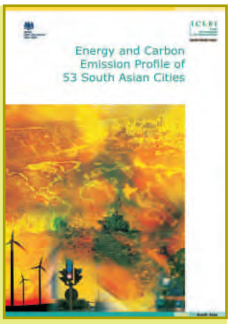

वर्ष 2012 के बाद 'वैश्विक जलवायु समझौता तथा कार्य परियोजना' के लिए दक्षिण एशियाई शहरों व स्थानीय सरकारों की कार्ययोजना ब्रिटिश उच्चायुक्त के सहयोग से आई.सी.एल.ई.आई. – दक्षिण एशिया व रा.न.का.सं. का एक संयुक्त प्रयास है जिसने 53 'दक्षिण एशियाई शहरों के लिए ऊर्जा स्थिति रिपोर्ट व कार्बन उत्सर्जन सूची' का विकास किया है। यह रिपोर्ट स्थानीय स्तर पर बेहतर मूल्यांकन करने में तथा भविष्य की कार्य योजना बनाने में सहायक होगी।

स्थानीय सरकार की जलवायु-कार्ययोजना दिसम्बर 2009

प्रो. चेतन वैद्य ने आई.सी.एल.ई.आई. – सततता हेतु स्थानीय सरकार द्वारा 10 दिसम्बर 2009 को कोपनगेहन, डेनमार्क में आयोजित 'स्थानीय सरकार की जलवायु-कार्ययोजनाओं' पर एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने भारत में जलवायु परिवर्तन तथा शहरी विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय शहरी कार्यक्रम पर प्रस्तुतीकरण दिया।

India Urban portal

इण्डिया अर्बन पोर्टल (www.indiaurbanportal.in) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत पीयर एक्सपीरियन्स एण्ड रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम की वेबसाइट है जो शहरी सूचना की उपलब्धता में वृद्धि करती है, नेटवर्क समुदाय तथा साधन का विकास करती है जो श्रेष्ठ, विश्वसनीय तथा वास्तविक आंकड़े व संपर्क उपलब्ध कराती है।

मेट्रोपोलिसः शहरी विकास प्रबंधन

मेट्रोपोलिस प्रमुख महानगरों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा औपचारिक रुप से मान्यता प्राप्त है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपसी जानकारी, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण संबंधी मुद्दों को बढ़ावा देना एवं समस्त बड़े शहरों और महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित आम मुद्दें हैं।

3–5 दिसम्बर 2009 तक मेट्रोपोलिस आयोग 2 की प्रथम बैठक हुई।

आयोग 2ः शहरी विकास प्रबंधन पर 3–5 दिसम्बर 2009 को नई दिल्ली में बैठक हुई। यह बैठक मैट्रोपोलिस, रा.न.का.सं. तथा आई.बी.एम. द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित की गई। इस बैठक में आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट, स्पेन, ईरान, भारत आदि से लगभग 20 शहरों ने भाग लिया। मेलबोर्न, सिडनी, कैरो, पुणे, उदयपुर, कोलकाता, मुम्बई, जमशेदपुर आदि पर प्रस्तुतीकरण दिए गए।

इन प्रस्तुतीकरणों ने आयोग 2 को शहरों के तेजी से हो रहे शहरीकरण और जीवंतता संबंधित मुद्दों की खोज, इसकी पहचान करने में निवेशकों के लिए शहरों को किस प्रकार आकर्षित बनाया जा सकता है, शहरों की जीवंतता को बढ़ाने, संरक्षण व प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कर (और क्या करना चाहिए) रही है, को समझने में सहायता दी। म्युनिसिपल वित्त, विरासत, गरीबों के लिए योजना, ई–शासन आदि जैसे विशेष क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई थी।

शहर–दर–शहर जानकारी

शांति नगर स्लम की यात्रा

जॉयनगर मोजिलपुर, झरग्राम, बर्दवान और हावड़ा पश्चिम बंगाल की नगर पालिकाओं से 5 सदस्यीय दल ने सिटी मैनजर्स एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश (सी.एमए. – एम.पी) की यात्रा की। इस यात्रा में फायर (डी) परियोजना के अंतर्गत रा.न.का.सं. ने सहयोग दिया।

अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान दल ने सी.एम.ए. – म.प्र. के अधिकारियों से भेंट की तथा योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों को देखा जैसे सड़को को चौड़ा करना और सौंदर्यीकरण तथा ऊर्जा–बचत प्रकाश व्यवस्था (एनर्जी–एफीशेन्ट लाईटिंग सिस्टम), बी.एस.यू.पी तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम के अंतर्गत कम लागत का आवास निर्माण परियोजना।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास था कुशल ठोस कचरा व म्युनिसिपल कार्यदल प्रबंधन हेतु वाहन–निगरानी प्रबंधन प्रणाली (व्हीकल ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम – वी.टी.एम.एस.) यह भोपाल नगर निगम (बी.एम.सी) के सार्वजनिक उपयोग के वाहनों का पता लगाने तथा प्रबंधन करने की एक विशेष सूचना प्रणाली है। भागीदारों ने उन्नत सेवा प्रदान करने तथा पूर्ण एकीकृत समाधान के प्रावधान के लिए बी.एम.सी. में म्युनिसिपल प्रशासनिक प्रणाली की मुख्य परियोजना भी देखी। कार्यदल भोपाल में शांति नगर स्लम भी गया।

गरीबों को जल एवं सफाई-व्यवस्था की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरी मॉडल : यू.एस.एड फायर (डी) का प्रयास

डी.एफ.आई.डी. के शहरी गरीबों के लिए मध्यप्रदेश शहरी सेवाएं (एम.पी.यू.एस.पी.) परियोजना के सहयोग से फायर (डी) परियोजना देवास नगर निगम को यह प्रदर्शित करने के लिए सहायता दे रही है कि एक शहर किस प्रकार शहरी नेटवर्क में गरीब निवासियों को शामिल करके अपनी शहरी जल आपूर्ति का विस्तार कर सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य – शहरी स्थानीय निकायों और स्लम समुदायों के संयुक्त कार्य के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों को मूल सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। फायर(डी) शहर के सबसे अधिक नौ अनुपयुक्त स्लमों में कार्य कर रहा है जिनको पूर्व परिक्षण सर्वेक्षण तथा व्यवहारिक अध्ययन के संचालन द्वारा खोजा गया था। इसके पश्चात् फायर(डी) ने एक विस्तृत स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाईन तथा संबंधित जल–नेटवर्क की लागत विनिर्देश विकसित किया जिसमें प्रत्येक स्लम के लिए सबसे उपयुक्त जल–स्रोत का मूल्यांकन शामिल हैं। इस पर, डी.एम.सी. ने फायर(डी) से इन नौ स्लमों में से चार में अन्य बुनियादी ढांचे के घटकों को डिजाईन करने का निवेदन किया। इस अतिरिक्त बुनियादी ढांचे में सीवरेज, सफाई–व्यवस्था, सड़कें व जल–निकासी शामिल हैं।

रा.न.का.सं. द्वारा आयोजित/समर्थित गतिविधियां

☼ **ब्राजीलियन शहरों पर कार्यशाला**

प्रो. इरमीनिया मैरीकेटो

प्रो. इरमीनिया मैरीकेटो, साओ पाओलो विश्वविद्यालय, श्री रेनेटो विलेला डॉस सैनटोस, उपसचिव वित्त, स्टेट ऑफ रियो व श्रीमती ऐनाक्लोडिया रोसबैक, सिटी एलियांस वालल ब्राजीलियन दल ने राष्ट्रीय शहरी नीति, नगर पालिकाओं को वित्त पोषण तथा ब्राजील में आवासीय नीति के रुझान पर उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुतीकरण दिया।

☼ **बुनियादी ढांचे हेतु वित्त पोषण के लिए शहरी भूमि कीमतों को खोलने पर कार्यशाला**

शहरी भूमि मूल्यों की संभावनाओं को खोलना विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण हेतु प्रमुख वैकल्पिक प्रयास के रुप में है। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट के वोलफेनसोन सेंटर फॉर डेवलपमेंट में 'मेकिंग सिटीज वर्क फॉर ग्रोथ प्रोजेक्ट' तथा इण्डिया अर्बन स्पेस फाउण्डेशन ने शहरी विकास मंत्रालय तथा आई.डी.एफ.सी.लि. तथा रा.न.का.सं. से भागीदारी में संयुक्त रुप से बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए भूमि मूल्यों को बढ़ाने में शामिल मुद्दों और चुनौतियों पर एक गहन और संरचित वार्ता का आयोजन किया। नीति पर आधारित दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें से 14-15 सितम्बर को बैंगलोर में तथा उसके बाद 16 सितम्बर 2009 को दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तकनीकी सत्रों में बाजार की भूमिका, पी.पी.पी. के लिए वित्तीय व्यवस्था, भारत के लाभकारी उपकरणों आदि का निरीक्षण किया। इजीप्ट, मेट्रो मनीला, बोगोटा, चिल, मुम्बई, अहमदाबाद व बैंगलोर से प्रमुख के अध्ययनों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

☼ **रीयल एस्टेट व आवास निर्माण पर कार्यशाला**

श्री एलाइन बरटोंड, भूतपूर्व प्रमुख शहरी नियोजक, विश्व बैंक ने शहरी नियोजन व भूमि बाजार पर संक्षिप्त इतिहास बताते हुए 'भूमि बाजारों, सरकारी हस्तक्षेप तथा आवास खरीदने की क्षमता' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। उनके प्रस्तुतीकरण में भारत, कोरिया, चीन व थाइलैंड से केस अध्ययनों के उदाहरण थे। इन अध्ययनों कें माध्यम से उन्होंने आय वर्ग व स्थिति द्वारा शहरी भूमि के बाजार वितरण के मार्ग बनाने की प्रक्रिया तथा भूमि की पूर्ति व उपयोग पर सरकारी कार्रवाई के प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने लागत, लाभ के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य की अनुसंधान कार्यसूची तथा विशेष नियमों के भूमि बाजार पर प्रभाव भी प्रस्तुत किया तथा सरकार के सामाजिक व पारिस्थितिक उद्देश्यों के साथ उनके सहयोग पर नियमित मूल्यांकन किया।

रा.न.का.सं. में श्री बरटॉड

रा.न.का.सं. के कार्मिकों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणः

☼ डा. देबोलिना कुण्डु, एसोसिएट प्रोफेसर ने डा. देबजानी घोष के साथ 'भारत में संपत्ति कर में नवप्रवर्तन' पर एक लेख में सह-लेखन किया, जिसे डा. कुण्डु ने वारसा में 15-16 अक्तूबर 2009 को क्षेत्रीय-सम्मेलन में प्रस्तुत किया।

☼ प्रो. चेतन वैद्य ने सी.एम.एस. वातावरण में 29 अक्तूबर 2009 में 'जलवायु-परिवर्तन का मुकाबला-भारतीय शहरों को कार्बन रहित करने की दिशा में' नामक कार्यशाला की अध्यक्षता की तथा 'सतत शहरों' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।

☼ श्रीमती सतमोहिनी रे. वरिष्ठ अनुसंधान फेलो ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 दिसम्बर को 'जलवायु-परिवर्तन तथा सतत शहरों' पर जिओग्राफी सोसायटी ऑफ मिरांडा हाऊस द्वारा आयोजित गतिविधि 'ग्लोब 2009' के भाग के रुप में एक प्रमुख प्रस्तुतीकरण दिया।

अंशदान

शहरी वित्त या अर्बन फाइनेंस की प्रति पाने के लिए अपना अनुरोध निम्नलिखित पते पर भेजे :-

संपादक
डा. मुकेश माथुर
सलाहकार
चेतन वैद्य
सहायक संपादक
डा. राजेश चन्द्रा
हिंदी रुपांतर
पूनम मल्होत्रा
टाइपिंग (हिंदी)
मीरा भागचंदानी
सहायक संपादक/डिजाइन व रुपरेखा
सतमोहिनी ईशा श्रीवास्तव रे
सचिवीय सहायक
सी.बी. पाण्डेय

संपादक
शहरी वित्त
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
कोर-4बी,
प्रथम व द्वितीय तल,
भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003
फोन 011-24627543
24643284
फैक्स - 24617513
ईमेल : niua@niua.org
वेबसाइट : www.niua.org